since its inception in September, 1952 upto the 31st March, 1967. The amount of Central assistance released to the Government of Gujarat under the Scheme upto the 31st March, 1967, is Rs. 699.99 lakhs.

(c) and (d). The Subsidised Industrial Housing Scheme is a continuing scheme and the State Governments have been authorised to sanction projects for construction of houses for industrial workers under this scheme. A sum of Rs. 17.00 lakhs has been provided by the State Government in their budget for 1967-68 for this scheme. According to the information received from the State Government, the following projects have been sanctioned by them during 1967-68 so far :—

Name of the construction Agency	No. of houses	Location	Approved Cost (Rupees in lakhs)
1. Gujarat State Road Transport Corporation	74	Mehsana	2·44
2. Varsha Industrial Co-operative Housing Society Ltd., Baroda . .	50	Baroda	2·68
3. Nure Ahwadi Co-operative Housing Society Ltd., Ahmedabad . .	25	Ahmedabad	1·22

खाद्य पदार्थों की शुद्धता

2428. **श्री ज्ञा० सुन्दर लाल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तेल, शहद तथा मसालों जैसे खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए साधन या सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चल रही खाद्य प्रयोगशाला में तेल, शहद और मसाले जैसे खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांचने की सुविधायें मौजूद हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में बड़ी सिंचाई परियोजनायें

2429. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुई है;

(ख) अब तक कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं;

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी, और

(घ) विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची में वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से महाराष्ट्र की स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) संशोधन की कमी के कारण साधारणतः सारे देश की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर प्रभाव पड़ा है । यह किसी हद तक महाराष्ट्र के बारे में भी सच है ।